मालदीव

1. संसार में अनेक ऐसे राष्ट्र-राज्य है जिन्हें दुनिया के मानचित्र पर ढूढ़ना लगभग असंभव है। इन्हें अति सूक्ष्म राज्य (माइक्रो स्टेट्स) का नाम दिया जाता है। इसे भूगोल की शब्दावली में एटोल कहते हैं। आकार, जनसंख्या एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि नगण्य होने के बावजूद अपनी भू-राजनैतिक स्थिति के कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सामरिक संवेदनशीलता के कारण महत्वपूर्ण समझे जाते हैं इन्हें अपनी छत्र-छाया या प्रभाव क्षेत्र में बनाये रखने के लिए महाशक्तियां सक्रिय रहती है और उनकी रस्साकशी का प्रभाव आस-पास के क्षेत्र पर अनिवार्यत: पड़ता है। इनमें से अधिकांश किसी महासागर के बीचो-बीच छोटे-छोटे द्वीप या द्वीपों के समूह हैं जिनमें से एक मालदीव है जो इस समय भारत की विदेशनीति के लिए एक विस्फोटक समस्या बन चुका है और ऐसा जान पड़ता है कि आने वाले वर्षों में भी एक जटिल चुनौती बना रहेगा।
2. मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह पर्यटन पर टिकी है। चूंकि खाने-पीने का सारा सामान (समुद्र में पकड़ी मछलियों, झींगों आदि को छोड़कर) बहुत दूर से आयात किया जाता है, इसलिए पर्यटन का विकास उन्हीं ग्राहकों की सामर्थ्य को देखकर हुआ है जो बेशुमार पैसा खर्च कर सकते हैं। एक छोटे से द्वीप से दूसरे छोटे से द्वीप तक जाने के लिए समुद्र पर उतर सकने वाले विमानों या स्पीड बोट का उपयोग किया जाता है और महंगे होटलों और स्पा में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारी विदेशी नागरिक है। राजधानी माले को छोड़कर पूरे देश में नाम लेने को भी कोई दूसरा शहर नहीं।
3. प्राचीन इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि हिंद महासागर के बीच में स्थित मालदीव द्वीप समूह बड़े देशों के नाविक व्यापारियों के लिए शरण स्थल बनता था, जब वह किसी खतरनाक तूफान में फंसते थे और मौसम सुधरने तक यहां लंगर डालते थे। जो पुरातात्विक अवशेष यहां मिलते हैं, वह इसी का प्रमाण है। स्थानीय आदिवासियों ने किसी सभ्यता का विकास यहां किया हो, इसका दावा नहीं किया जा सकता। मध्ययुग में यहां खूंखार समुद्री तस्करों ने अपना अड्डा बनाया था जो आस-पड़ोस से गुजरने वाले बेड़ों को अपना निशाना बनाकर लूट-पाट करते थे। 18-19 वीं सदी में एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और पश्चिमी औपनिवेशिक ताकतों की नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता इन तस्करों की नहीं रही। भारत पर अपना आधिपत्य करने के बाद बर्तानवी नौसेना का वर्चस्व पूरे हिन्द-महासागर पर बना रहा और मालद्वीव एक संग्रक्षित पराधीन, पूरी तरह पराश्रित द्वीप समूह ही रहा।
4. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ और 1960 के दशक में अनेक नवोदित राज्य स्वाधीन हुए। संयुक्त राष्ट्र के दिसंबर, 1960 में पारित प्रस्ताव में औपचारिक रूप से उपनिवेशवाद के अंत की घोषणा की। और क्रमश: 1970 के अंत तक हिन्द-महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित अनेक सूक्ष्म राज्य स्वतंत्र हो गए। इसके बाद भी कई दशक तक मॉरीशस, बोर्नियों, पापुवा न्यूगिनी जैसे बड़े देश ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित रहे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड के पूर्व में टोंगा, समोआ, नाउरू, सोलोमन और क्रिसमस द्वीप आदि की तरफ नृत्रत्व शास्त्रियों और विश्लेषकों की नज़र तभी जाती थी, जब किसी महाशक्ति के परमाणविक परीक्षण यहां रहने वालों के लिए वंशनाश का संकट उत्पन्न करते थे।
5. हाल के वर्षों में भी इनकी चर्चा धरती के तपने के साथ प्रलयकारी मौसम बदलाव से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट ही होती रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समुद्र के जल की सतह दो इंच भी ऊपर उठती है तो लगभग यह सभी देश समुद्र के गर्भ में समा जाएंगे।
6. भारत की भूमि का अभिन्न अंग अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप एटोल हैं। मालदीव के सबसे नजदीकी पड़ोसियों में एक भारत है और भारत के साथ उसके नाते अभी एक दशक पहले तक बहुत करीबी रहे हैं। भारत ने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव के आधारभूत ढांचे के निर्माण में मदद की है, बल्कि वहां सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वूपर्ण योगदान दिया है। यह सच है कि भारत में यह सबकुछ शुद्ध परोपकारी नज़रिए से नहीं किया, बल्कि अपने सामरिक हितों को सुरक्षित रखने

के लिए ही किया, तथापि कुलमिलाकर इसका नतीजा भारत और मालदीव के बीच संबंधों को दोस्ताना और मजबूत बनाने वाला ही रहा है। जब लगभग एक दशक पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की तख्ता पलट की साजिश कुछ असंतुष्ट तत्वों ने रची थी तब उनकी रक्षा उनकी मांग को स्वीकार कर भारतीय नौसेना के कमांडो ने ही की थी।

7. विडंबना यह है कि तब से मालदीव के शासकों को इसबात की आशंका होने लगी है कि भारत कभी भी उस देश की राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप की क्षमता रखता है और अपने मनोनकूल सत्ता परिवर्तन करने की चेष्टा कर सकता है। भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अब्दुल गयूम तभी से प्रयत्नशील हो गए और भारत को 'संतुलित' करने के लिए उन्होंने दूसरे राजनयिक विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की यह सोच निर्मूल सिद्ध हुई कि गाढ़े वक्त पर भारत से मिली मदद के कारण गयूम उसके मित्र बने रहेंगे। अब्दुल गयूम का रवैया क्रमशः मैत्री से उदासीन और फिर किंचित, असंतुष्ट बैर भाव वाला बनता गया। भारत ने अतिक्षय आत्मविश्वास के कारण उस घटनाक्रम को अनदेखा किया जो चेतावनी दे रहा था। पाकिस्तान के गठजोड़ कर चीन इस इलाके में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था। भले ही भारत मालदीव की वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता को ध्यान में रख असाधारण धैर्य का परिचय देती है उसे मनोवांछित परिणाम नहीं मिले हैं।

8. राष्टपति यामिन की प्रतिक्षाह यह असंवैधानिक सरकार का यह मानना है कि भारत उनके प्रमुख प्रतिद्वद्वी नसीद की समर्थक है। अब्दुल गयूम के कार्यकाल के अंत में जो कुछ वैमनस्य सतह पर आ रहा था, उसे दूर करने में नसीद का योगदान रहा है। सत्ता ग्रहण करते ही यामिन ने उन्हें जेल में डाल दिया था, फिलहाल वह विदेश में प्रवास कर रहे हैं। नसीद यामिन के सबसे कड़े और आक्रामक आलोचक है जिनका आरोप है कि यामिन चीन के हाथों नाचने वाला कठपुतलाभर है, जिन्होंने असंवैधानिक कानून बना मालदीव की भूमि खरीद उनका स्वामी बनने के अधिकार विदेशियों को दे दिया है। इस जमीन पर मालदीव की संप्रभुता बहुत सीमित लगभग नगण्य रह जायेगी। (अनेको दूसरे देशों में भी विशेष आर्थिक क्षेत्र मे या निर्यात पट्टी में विदेशियों को तरह-तरह के करो की रियायते और स्थानीय कानून की बेड़ियों का छुटकारा दिया जाता है, परन्तु मालदीव के सूक्ष्माकार को देखकर भूमि पर संपूर्ण स्वामित्व गवाने के बाद इस देश की संप्रभुता के लिये जो संकट खड़ा होता नज़र आ रहा है उसकी तुलना किसी और देश से नहीं की जा सकती।

आज बड़े पैमाने पर मुँहमाँगे दाम देकर अपनी मनपसंद जमीन खरीद सकने की क्षमता सिर्फ चीन की हैं और उसकी दिलचस्पी मालदीव के उन्हीं हिस्सों पर है जहां वह या तो सामरिक महत्व की हवाई पट्टी का निर्माण कर सकता है या पनडुब्बियों का रखरखाव या उनकी तैनाती के लिये बंदरगाह आदि की व्यवस्था कर सकता है।

9. इन आरोपों को सिर्फ यह कहकर खारिज़ नहीं किया जा सकता कि इन्हें राजनैतिक पक्षधरता के कारण राष्ट्रपति के चुनाव में हारा हुआ एक उम्मीदवार लग रहा है। जिस समय यामिन चुनाव जीते थे चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवालियां निसान लगाये गये थे। पद ग्रहण करने के बाद से भारतीय ही नहीं दूसरे अर्न्तराष्ट्रीय पत्रकारों के आने और उन्हें काम करने देने पर कड़ी रोक लगाई गई है और यह आरोप निराधार नहीं कि तमाम फैसले बिना पारदर्शिता के और कुनबापरस्त और मुनाफाखोरी के लालच में लिए जा रहे हैं।

10. मालदीव में जो मौजूदा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए भारत का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि यामिन का निरंकुश आचरण ही जिम्मेदार है। उस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह फैसला सुनाया कि जेल में बंद तीन सांसदों को रिहा किया जाए और संसद की कार्यवाही में भाग लेने दिया जाये तो यामिन सरकार के लिये अल्पमत में आने का खतरा पैदा हो गया। पूर्व राष्ट्रपति अभी जेल में बंद है और उनकी पुत्री ने जो अबतक यामिन सरकार में शामिल थी राजनैतिक उथल-पुथल को देखते इस्तीफा दे दिया है। मालदीव की आम जनता मछुवारों की है और छोटा सा सर्वेष्ठी वर्ग ही वहां राज करता रहा है और इस शासकवर्ग में रक्त और शादी के आधार पर रिश्तेदारी का जाल बुना है। इस वक्त जो फूट नज़र आती है वह चीन समर्थकों और चीन का विरोध करने वालों के बीच की है। इसका आधार सैद्धांतिक नहीं, बल्कि एक परिवार के मुट्ठीभर सदस्यों द्वारा तमाम अन्तर्राष्ट्रीय सौदा का सारा लाभ अपने तक ही सीमित रखने की प्रवृत्ति है।

11. जहांतक विचारधारा का सवाल है मालदीव में यह संघर्ष साम्यवाद बनाम पूंजीवाद वाला नहीं, बल्कि कट्टरपंथी असहिष्णु आक्रामक इस्लाम और सहनशील, मानवीय और तरक्की पसंद इस्लाम के बीच जारी है। मालदीव की लगभग पूरी आबादी मुसलमानों की है और पारंपरिक रीति-रिवाजों का अनुशरण करने के बावजूद वह कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहे हैं। हाल के वर्षों में सउदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ-साथ मजहबी कट्टरपंथी का निर्यात भी इन देशों से होता रहा है। दुर्भाग्यवश भारत सरकार इस बारे में सचेत नहीं रही। इसी का नतीजा है कि आज यामिन खुद को अपने समर्थकों के सामने

दीन के रखवाले के रूप में पेश कर सकते हैं और उनके लिये नशीद को अल्पसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़क धर्मनिरपेक्ष अर्थात इस्लाम विरोधी भारत के एजेंट के रूप में बदनाम करना आसान हो जाता है। यह ठीक है कि भारत मालदीव के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर वह इस दलील को पत्थर की लकीर मान अपने सामरिक हितों की बली भी नहीं दे सकता।

12. भू-राजनैतिक यथार्थ यह है कि चीन को अपने नौसैनिक दस्ते या वायुयान के माध्यम से मद्द मालदीव तक पहुंचाने के लिये कम से कम 17-18 घण्टे का समय चाहिए। जबकि भारत जरूरत के समय 4-5 घण्टों में वहां पहुंच सकता है। जब मालदीव सुनानी में डूब रहा था, तब भारत इससे भी कम समय में वहां राहत पहुंचा सका था। संकट यह नहीं कि मालदीव में कट्टरपंथी सरकार है। हमारी चिंता का असली विषय यह है कि यह सरकार पाकिस्तान से प्रायोजित दहशतगर्दी की तरफ आंखे मूंदे है और अपने राजनैतिक विरोधियों का दमन करने के लिए अन अराजक तत्वों को शह दे रही है। मालदीव की सरकार यह कह अपनी असमर्थता जता सकती है कि सैकड़ों छोटे-छोटे द्वीपों के कोने-अतरे या छोटी-बड़ी खाड़ी चौंकीदारी करना असंभव है और यही स्थल भारत के लिए गंभीर सामरिक संकट पैदा कर सकती। जो बात सबसे सहज थी वह भारत की नौसेना को तस्करों और आतंकवादी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए मद्दगार बनाना। ऐसी हर पेशकश को चीन के दबाव में मालदीव ठुकराता रहा है।

13. दो-तीन वर्ष पहले भारत की एक कंपनी द्वारा हवाई अड्डे का सौदा खारिज कर यामिन की सरकार ने यह ठेका चीन को दे दिया। उसके बाद दूरस्त एक द्वीप में पनडुब्बियों के काम आने लायक जगह भी चीन को बंदरगाह सुधान निर्माण के नाम पर दी जा चुकी है। कुछ ही दिन पहले जब भारत ने दक्षिण एशिया देशों के हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव को निमंत्रण दिया तो मालदीव ने बहुत ही अपमानजनक ढंग से इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि फिलहाल हमारे देश में हालात ऐसे नहीं कि हम इस अभ्यास में सरीख हो सके। हमें सैनिक और नौसैनिक दस्तें कभी कभी अन्यत्र तैनात करने पड़ सकते हैं।

14. वास्तव में मालदीव की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वहां आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक बताते हुए यह राय व्यक्त की है कि यह घटनाक्रम जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं समझा जा सकता। यहां दो बाते तत्काल जोड़ने की जरूरत है। भारत की चिंता इस बात को लेकर नहीं कि मालदीव में जनतांत्रिक सरकार नहीं। हमारी आशंका यह है कि मौजूदा सरकार के संरक्षण में मालदीव में कार्यरत भारतीय शत्रु हमारे जनतंत्र के लिए- एकता और अखण्डता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। निश्चय ही यामिन का आचरण ऐसे आशंकाओं को जन्म देता है। उन्होंने न केवल अपने देश में न्यायपालिका से मुठभेड़ का रास्ता चुना है, बल्कि उन जजों को भी बर्खाश्तकर बंदी बनाने का आदेश दिया है जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया था। यामिन की अपनी राय में यह जज कानूनी तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे, पर जिस तरह मालदीव के चारो ओर वह एक अभेद्य- अपारदर्शी पर्दा डालना चाहते हैं उसके मध्य नज़र उनसे सहमत होना कठिन है।

15. जो लोग यह सोचते थे कि रत्तीभर का मालदीव दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले महान भारत के लिए आखिर कैसे परेशानी का सबब बन सकता है, उनको मिलाने के लिए अबतक बहुत कुछ हो चुका है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है- भारतीय विदेश सचिव द्वारा लिखा गया एक पत्र द्वारा दी गई सलाह को मानते हुए भारत सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस माह के अंत में आयोजित होने वाले किसी ऐसे समारोह में हिस्सा न ले जहां दलाईलामा उपस्थित हो। वह वर्ष भारत में तिब्बती शरणार्थियों की आगमन की 60वीं सालगिरह मना रहा है और यह निर्देश इस बात को देखते हुए बेहद अटपटा लगता है, क्योंकि अबतक जब भी चीन ने दलाईलामा को लेकर भारत सरकार को कोई भी आपत्ति जताई है हमने हमेशा यही दो टूक उत्तर दिया है कि दलाईलामा हमारे सम्मानीय अतिथि है और उन्हें शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों-सामाजिक समारोहों में भाग लेने की पूरी आजादी है। इस बार अगर हम चीन की घुड़की के सामने झुकते नज़र आ रहे हैं तो शायद सिर्फ इसलिए कि चीन ने मालदीव को लेकर यह बयान देते देर नहीं लगाई कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी पड़ोसी के साथ मुठभेड़ की संभावना बढ़ती है।

जाहिर है कि यह बयान सास को कहना और बहू को सुनाने वाले अंदाज में लिया गया था। डोकलाम में आमने-सामने मुठभेड़ वाले अंदाज में दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती जारी है और दक्षिणी चीनी सागर में अर्थात हिंद महासागर के उत्तरी भाग में चीन के विस्तारवाद का भारतीय प्रतिरोध भी चीन को नागवार गुजरता रहा है। यही नतीजा निकालना तर्कसंगत लगता है कि कम से कम फिलहाल भारत ने चीन को ललकारने का या उसके राजनयिक प्रतिरोध का फैसला बदल दिया है।